

संख्या : / 111(3)/16-06(एस0पी0ए0)/2014 टी0सी0-11

प्रेषक,

डी0एस0 गबर्वाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक: 16 नवम्बर, 2016

विषय:-प्राकृतिक आपदा एस0पी0ए0/एस0पी0ए0, आपदा 2013 के अन्तर्गत सड़क एवं सेतुओं के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 224/34 बजट(एस0पी0ए0-पुनर्निर्माण)/2016-17 दिनांक 12.5.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा वित्त मंत्रालय-भारत सरकार के पत्र संख्या-44 (21) PFI/2014-1334, दिनांक 27 जनवरी 2015 एवं पत्र संख्या-44 (21) PFI/13-1421, दिनांक 13 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं बादल फटने आदि के कारण जनपद उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों/पुलियों के पुनर्निर्माण के अन्तर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन की विभागीय तथा शासन स्तर पर गठित टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि के सापेक्ष तीन कार्य/योजनाओं यथा- " जिला उत्तरकाशी में मोरी विकास खण्ड के नैटवाड़ सांकरी राज्य मार्ग सं० 48 मोटर मार्ग के कि०मी० 01 से 26 तक सुधार एवं डामरीकरण का कार्य, लागत रु० 709.13, एस0पी0ए0-आर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुरोला में सांकरी-जखोल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण सुधार एवं डामरीकरण का कार्य, लागत रु० 519.59 तथा जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के मोरी-नैटवाड़-सांकरी मोटर मार्ग के कि०मी० 20 से आगे सांकरी तक परिवर्तित समरेखण मोटर मार्ग के कि०मी० 01 से 09 तक डामरीकरण का कार्य, लागत रु० 390.92 सहित कुल लागत रु० 1619.64 (रुपये सोलह करोड़ उन्नीस लाख चौसठ हजार मात्र) की निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1-वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी0एस0एस0/केन्द्र पोषित सड़क एवं सेतुओं के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
- 2-सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं/कार्यों पर किया जायेगा, जिनके लिये यह प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 3-निर्गत की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यों हेतु धनराशि का आहरण व व्यय शासन के बजट आवंटन सम्बन्धी शासनादेश में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
- 4-उक्त व्यय में बजट मैन्युअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 5-यह धनराशि आपदा 2013 में हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यों के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा, इसके लिये सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- 6-जहाँ आवश्यक हो, कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

- 7-विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पत्र पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 8-कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9-कार्य करने से पूर्व अनुमन्त्र दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 10-विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- धनराशि का आहरण, सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
- 12-उल्लिखित कार्य/योजनाओं पर मानकानुसार यथा प्रक्रिया भारत सरकार/उच्चाधिकार प्राप्त समिति आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। आगणन में स्वीकृत डिजाइन, मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।
- 13-यदि उक्त कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजना किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 14-निर्गत की जा रही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित कार्यों सापेक्ष धनावंटन हेतु कार्य/कार्यों के प्रोजेक्ट सं0 एवं प्रोजेक्ट कोड सहित, प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि आपदा प्रबन्धन विभाग से समयान्तर्गत धनावंटन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा सकें।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80 सामान्य-800-अन्य व्यय-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-02 एस0पी0ए0/एस0सी0ए0 (आपदा 2013) के अन्तर्गत सड़क एवं सेतु निर्माण हेतु अनुदान-24-वृहत निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत होगा।
- 3- यह प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, एस0पी0ए0(आर0) के नोडल विभाग अर्थात् आपदा प्रबन्धन विभाग की सहमति दिनांक 09.03.2016 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डी0एस0 गर्बाल)
सचिव।

संख्या : 663 / 111(3)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग को उपरोक्त के सन्दर्भ में।
- (2) अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- (3) महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- (4) सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- (5) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी।
- (6) निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- (7) वित्त अनुभाग-02/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- (8) राज्य नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- (9) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
- (10) लोक निर्माण अनुभाग-01/02, उत्तराखण्ड शासन।
- (11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।